रोम, इटली में 'वैश्विक महामारी से उत्पन्न सामाजिक और रोजगार संबंधी संकट के समाधान के प्रयास' विषय पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष का Intervention.

माननीय सभापति जी और शिष्टमंडल के माननीय सदस्यगण

---

1. साथियो, कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न किया है। इस महामारी के कारण अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में भी संकट उत्पन्न हुए हैं। इस महामारी का सामना करने में हमने दो लक्ष्यों, अर्थात जीवन बचाने और आजीविका बचाने पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया है।

2. मैं आज यहां उस भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां लोकतंत्र की हजारों वर्षों की गौरवशाली परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को, भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारे विविधतापूर्ण, सशक्त लोकतांत्रिक देश में इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं।

3. विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश की संसद के रूप में हमारा प्रयास है कि हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए एक बेहतर विश्व का निर्माण करें।

4. कोविड महामारी के दौरान भी भारतीय संसद ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए चार ऐतिहासिक Labour Laws को पारित किया जिससे रोजगार सृजन के अलावा Wage Security, Social Security एवं Job Security को बढ़ावा मिलेगा।

5. इसके अंतर्गत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। इस पोर्टल में उन श्रमिकों का Verified डाटा कलेक्ट करने का प्रावधान है जिससे लगभग 380 मिलियन श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन हो पायेगा। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा App based श्रमिकों, Gig and Platform Workers को भी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह पेंशन, बीमा, चिकित्सा, प्रोविडेंट फंड जैसी सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी।

6. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 420 बिलियन डॉलर का विशेष पैकेज दिया गया है। इसका मुख्य लाभ Rural Economy को मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में 67 (Sixty Seven) मिलियन महिला सदस्य सक्रियता से कार्य कर रही हैं।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अधिक बढाने की दृष्टि से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार किया गया है और अब इस योजना के तहत 150 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

8. अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए MSME सेक्टर का सशक्त होना आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना करते हुए इस वर्ष इसे 157 बिलियन रूपये कर दिया गया है।

9. हमारा उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का है जो वैश्विक सप्लाई चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपना योगदान करेगा।

10. सरकार की सुशासन एवं पारदर्शिता की नीति के कारण भारत आज विश्व के top 100 Ease of Doing Business वाले देशों में आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत विश्व का top investment destination होगा।

11. देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए National Infrastructure Pipeline जैसी महत्वाकांक्षी आधारभूत योजनाएं आरंभ की गई हैं जिससे न केवल Economic Growth बढ़ेगी बल्कि देश में बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण भी होगा।

12. आपको यह सुनकर गर्व होगा कि भारत में पहली बार 430 मिलियन लोगों को सीधे बैंकिंग सिस्टम से जोडा गया है। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत 165 मिलियन नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

13. मेरा मानना है कि भविष्य में आने वाली वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व को 'एक कुटुम्ब' के रूप में मानकर हमें एक integrated and coordinated strategy बनानी होगी। इसमें सभी संसदों का योगदान जरूरी है। हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि विकास की जो नीतियां बनें, वह सर्व-समावेशी हो, सर्व-स्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो तथा सर्वपोषक हो।

14. इस प्रकार से तैयार की गई सुविचारित एवं समन्वित नीतियों के विषय में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवाद एवं चर्चा होनी चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित suitable and sustainable साझा रोडमैप तैयार किया जा सके जिसके माध्यम से हम किसी भी वैश्विक आपदा का मुकाबला कर सकें।

15. मेरा G-20 देशों की संसदों से आग्रह है कि हम सब अपने लिए और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, एकजुट होकर किसी भी आपदा या चुनौती का मुकाबला सामूहिकता की भावना से करें ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

धन्यवाद।